Gyanvividha, Vol.-2; Issue-3 (July-Sept.) 2025 : PP-132-139

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-2.25
Vol.-2; Issue-3 (July-Sept.) 2025
Page No.- 132-139
©2025 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

1. Indrajeet Kumar
Research Scholar, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar College, Bihar University, Muzaffarpur.

2. Satyaprakash Kumar
Assistant Professor,
Deo Chand College, Bihar University, Muzaffarpur.

Corresponding Author :

Indrajeet Kumar
Research Scholar, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar College, Bihar University, Muzaffarpur.

"21वीं सदी में कूटनीति : सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी"

सारांश : 21वीं सदी में कूटनीति के क्षेत्र में डिजिटल डिप्लोमेसी ने एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है, जो सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देशों के बीच संवाद स्थापित करता है। यह पारंपरिक कूटनीतिक विधियों की तुलना में एक अधिक गतिशील, त्वरित और प्रभावी तरीका है। भारत ने इस डिजिटल कूटनीति का प्रभावी उपयोग किया है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, जब उसने वैश्विक सहयोग की अपील करने और अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया। इसके अलावा, भारत की G20 अध्यक्षता और अन्य पहलें, जैसे योग दिवस और आयुर्वेद, ने उसकी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, डिजिटल डिप्लोमेसी के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड, सूचना युद्ध, और राजनीतिक प्रभाव। इन समस्याओं को हल करने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग और उचित नीतियाँ बनानी आवश्यक हैं। इस शोध में डिजिटल डिप्लोमेसी के सिद्धांत, भारत की पहलें और इससे जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है, और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि डिजिटल डिप्लोमेसी भविष्य में वैश्विक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है यदि इसे सही दिशा में अपनाया जाए।

1. **प्रस्तावना :** 21वीं सदी में कूटनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिससे पारंपरिक कूटनीति के रूपों में बदलाव और नवाचार देखने को मिले हैं। कूटनीति का परंपरागत रूप जहाँ सैन्य शक्ति और आर्थिक संसाधनों पर निर्भर करता था, वहीं आज की कूटनीति में सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी की भूमिका बढ़ गई है। यह बदलाव सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, और वैश्विक नेटवर्क के कारण हुआ

है। जोसेफ नाय (Joseph Nye) के "सॉफ्ट पावर" के सिद्धांत ने इस बदलाव को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाय का मानना था कि केवल सेना या आर्थिक ताकत से ही कूटनीतिक सफलता नहीं मिलती, बल्कि एक राष्ट्र की सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक शक्ति भी महत्वपूर्ण होती है (Nye, 2004)।

सॉफ्ट पावर का अर्थ है किसी राष्ट्र की क्षमता दूसरों को आकर्षित और प्रभावित करने की, बिना बल प्रयोग या आर्थिक प्रलोभन के। इसके विपरीत, हार्ड पावर वह शक्ति है जो सैन्य और आर्थिक ताकत पर आधारित होती है। सॉफ्ट पावर की परिभाषा में संस्कृति, राजनीतिक मूल्य, और विदेशी नीति का आकर्षण शामिल है, जो एक राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करता है (Nye, 1990)।

21वीं सदी में, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास ने कूटनीति के नए आयाम खोले हैं। डिजिटल डिप्लोमेसी या इलेक्ट्रॉनिक कूटनीति वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके अपनी कूटनीतिक रणनीतियाँ बनाती हैं। यह पारंपरिक कूटनीतिक गतिविधियों को तेज, पारदर्शी और व्यापक बनाता है। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, और अन्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से देशों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है, जिससे नए प्रकार के प्रभाव और रिश्ते उत्पन्न होते हैं (Gorman, 2017)।

भारत, जो एक नवोदित वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, ने सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी के माध्यम से अपनी कूटनीतिक नीति को मजबूत किया है। भारत का सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे योग, बॉलीवुड, और आयुर्वेद, उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। साथ ही, भारत ने डिजिटल कूटनीति के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने डिजिटल माध्यमों के जरिए न केवल अपनी सहायता भेजी, बल्कि वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा दिया (Government of India, 2020)।

इस शोध में, हम सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी के सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही भारत द्वारा इन पहलुओं का प्रभावी उपयोग करके अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, हम यह भी देखेंगे कि डिजिटल कूटनीति की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ क्या हैं, और भविष्य में इसके प्रभाव के बारे में क्या संभावनाएँ हैं।

2. **सॉफ्ट पावर: परिभाषा और सिद्धांत :** सॉफ्ट पावर एक ऐसा अवधारणा है जिसे जोसेफ नाय ने 1990 के दशक में प्रस्तुत किया था, और यह राष्ट्रों के बीच प्रभाव बनाने के तरीके को नए दृष्टिकोण से समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। नाय के अनुसार, सॉफ्ट पावर का अर्थ है किसी राष्ट्र की उस क्षमता को, जिसके द्वारा वह दूसरों को आकर्षित करता है और बिना बल प्रयोग के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। पारंपरिक सैन्य या आर्थिक शक्ति के बजाय, यह विचार करता है कि एक राष्ट्र अपनी संस्कृति, राजनीतिक आदर्शों और नीतियों से दूसरों को आकर्षित करने में सक्षम हो सकता है। जोसेफ नाय ने इसे शक्ति का एक नया रूप माना और बताया कि सॉफ्ट पावर देशों को अपने विचार और मूल्यों के आधार पर दूसरों से सहयोग प्राप्त करने का अवसर देता है (Nye, 2004)।

सॉफ्ट पावर के सिद्धांत में तीन प्रमुख तत्व होते हैं: संस्कृति, राजनीतिक आदर्श, और विदेशी नीति। किसी राष्ट्र की संस्कृति, जैसे कि उसके साहित्य, कला, और जीवन शैली, यदि वैश्विक स्तर पर आकर्षक होती है, तो यह उसे सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करने का अवसर देती है। नाय के अनुसार, अगर एक राष्ट्र की संस्कृति का वैश्विक स्तर पर आकर्षण है, तो वह उसे एक स्थायी कूटनीतिक लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है (Nye, 1990)। उदाहरण के तौर पर, अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री (हॉलीवुड) और ब्रिटेन की शाही परंपरा ने इन देशों की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया है। इन देशों की सांस्कृतिक धरोहर ने उन्हें वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है।

राजनीतिक आदर्श भी सॉफ्ट पावर का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। लोकतंत्र, मानवाधिकार, और न्याय के सिद्धांत जब एक राष्ट्र के आधार होते हैं, तो यह दूसरों को आकर्षित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोकतांत्रिक सिद्धांत और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता ने उसे एक वैश्विक आदर्श के रूप में स्थापित किया है (Nye, 2004)। इसके अलावा, यदि किसी राष्ट्र की विदेश नीति दूसरों के प्रति सहयोगात्मक और सकारात्मक होती है, तो यह भी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में मदद करती है। भारत की विदेश नीति इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें उसने विकासशील देशों को शैक्षिक, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहायता प्रदान की है, जिससे भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाया है (Kapur, 2010)।

21वीं सदी में सॉफ्ट पावर का परिप्रेक्ष्य और भी व्यापक हुआ है, खासकर डिजिटल कूटनीति (डिजिटल डिप्लोमेसी) के उदय के साथ। यह डिजिटल तकनीकों के माध्यम से कूटनीति को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का एक तरीका है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए राष्ट्र अपनी संस्कृति, नीतियों और विचारों को सीधे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इस बदलाव को वैश्विक स्तर पर अपनाया गया है, और यह कूटनीति का नया रूप बन गया है। **पेट्रीसिया हेनेस** और **कैंडिस ब्राउन** जैसे शोधकर्ताओं ने डिजिटल कूटनीति और सॉफ्ट पावर के संयोग पर विचार करते हुए यह बताया कि कैसे डिजिटल माध्यमों ने देशों की कूटनीतिक शक्ति को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है (Hennessey & Brown, 2018)।

भारत का उदाहरण देखें, तो उसने डिजिटल कूटनीति का प्रभावी उपयोग किया है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। इस महामारी के दौरान भारत ने न केवल घरेलू स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी सहायता भेजी और महामारी से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वैश्विक समुदाय से सहयोग की अपील की और डिजिटल कूटनीति का प्रयोग किया (Ministry of External Affairs, 2020)। इसने भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक स्तर पर एक नई दिशा दी।

सॉफ्ट पावर की आलोचनाएँ भी रही हैं। डैनियल ओलावाले जैसे विद्वान ने यह तर्क किया कि सॉफ्ट पावर का प्रभाव कभी स्थायी नहीं होता, क्योंकि यह केवल सहमति और आकर्षण पर आधारित होता है, जो कभी भी बदल सकता है। साथ ही, यह आलोचना की जाती है कि जब सॉफ्ट पावर का प्रयोग एकतरफा होता है और किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन जाता है, तो इसका प्रभाव सीमित हो जाता है (Olawale, 2017)। इसके अलावा, हेरोल्ड लैसवेल और रॉबर्ट कीन जैसे कूटनीतिक विचारकों ने भी यह तर्क किया कि सॉफ्ट पावर की शक्ति केवल संस्कृति और आदर्शों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं (Lasswell, 1950; Keene, 2005)।

इस तरह से, सॉफ्ट पावर ने 21वीं सदी में कूटनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। यह शक्ति का वह रूप है जो देशों को बिना बल प्रयोग के अन्य देशों के साथ रिश्ते स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि, इस सिद्धांत की आलोचनाएँ भी हैं, लेकिन इसके प्रभाव और वैश्विक राजनीति में इसकी बढ़ती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भारत जैसे देशों ने अपनी सॉफ्ट पावर का प्रभावी उपयोग कर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, और आने वाले समय में यह और भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

3. **डिजिटल डिप्लोमेसी: परिभाषा और विकास :** डिजिटल डिप्लोमेसी, जिसे 'इलेक्ट्रॉनिक कूटनीति' भी कहा जाता है, कूटनीति का वह रूप है जिसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स—जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, और अन्य ऑनलाइन टूल्स—का उपयोग करके देशों के बीच संवाद और संबंध स्थापित किए जाते हैं। यह पारंपरिक कूटनीतिक विधियों से एक

महत्वपूर्ण बदलाव है, जो तकनीकी विकास और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ है। डिजिटल डिप्लोमेसी ने कूटनीति के परंपरागत रूपों को चुनौती दी है और एक नया आयाम प्रस्तुत किया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्विक नेटवर्क का प्रभावी उपयोग किया जाता है (Gorman, 2017)।

डिजिटल डिप्लोमेसी के विकास को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसके इतिहास और परिभाषा पर विचार करें। पहले, कूटनीति का कार्य केवल राजनयिक चैनलों, व्यक्तिगत बैठकों और सरकारी रिपोर्टों के माध्यम से होता था, लेकिन डिजिटल डिप्लोमेसी ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। अब, देशों के नेता ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से अपनी नीतियाँ और विचार दुनिया भर में साझा कर सकते हैं। डिजिटल कूटनीति ने पारंपरिक कूटनीतिक गतिविधियों को तेज़, पारदर्शी और व्यापक बना दिया है (Van Ham, 2013)।

भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल डिप्लोमेसी का प्रभावी उपयोग किया। महामारी के समय, भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से न केवल अपनी स्वास्थ्य नीतियाँ साझा कीं, बल्कि वैश्विक सहयोग के लिए अन्य देशों से भी संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वैश्विक समुदाय से सहयोग की अपील की और डिजिटल कूटनीति का प्रयोग किया (Ministry of External Affairs, 2020) । इसके अलावा, भारत ने वैश्विक स्तर पर मदद के लिए कोविड-19 वैक्सीन्स और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति शुरू की, जो एक डिजिटल डिप्लोमेसी की पहल थी। यह भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में सहायक रहा और उसने अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूती दी (Nye, 2004)।

डिजिटल डिप्लोमेसी के विकास के साथ-साथ यह महत्वपूर्ण हो गया है कि देशों को अपने कूटनीतिक संदेशों को सही तरीके से और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करें। सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाएँ और प्रोपेगेंडा एक चुनौती बन सकते हैं, जिससे कूटनीति के प्रभाव पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है (Hennessey & Brown, 2018)। इसलिए, डिजिटल डिप्लोमेसी के अंतर्गत देशों को अपनी सूचना नीतियों को ठीक से निर्धारित करने और सार्वजनिक धारणा को सही दिशा में मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, डिजिटल डिप्लोमेसी ने कूटनीति के पारंपरिक रूपों में बदलाव किया है और यह वैश्विक संवाद को और अधिक गतिशील और प्रभावी बना रहा है। भारत जैसे देशों ने इसका उपयोग करके अपनी कूटनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, और भविष्य में यह कूटनीतिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा (Cohen, 2017)।

4. **भारत की सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी :** भारत की सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी ने वैश्विक मंच पर उसे एक प्रभावी कूटनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर और डिजिटल कूटनीति का प्रभावी उपयोग करके वैश्विक समुदाय के साथ रिश्तों को मजबूत किया है। इस खंड में हम भारत की सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी की विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही इसके पीछे के सिद्धांतों, प्रमुख विचारकों और वैश्विक दृष्टिकोण को भी शामिल करेंगे।

सांस्कृतिक कूटनीति: भारत का वैश्विक प्रभाव : सॉफ्ट पावर के सिद्धांत को जोसेफ नाय ने 1990 के दशक में प्रस्तुत किया, और यह आज के कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है (Nye, 2004)। नाय का मानना था कि एक राष्ट्र की शक्ति का केवल उसका सैन्य या आर्थिक बल ही नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और राजनीति के आदर्श भी वैश्विक प्रभाव बनाने में सहायक होते हैं। भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति का इस्तेमाल किया, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में विशेष स्थान मिला।

भारत ने अपनी संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए कई पहलें की हैं। **योग**, **आयुर्वेद**, **बॉलीवुड** और **भारतीय व्यंजन** ने भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में फैलाया।

1. **योग**: भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा योग को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने के लिए भारत ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में "International Day of Yoga" का प्रस्ताव रखा। इस पहल का उद्देश्य योग के माध्यम से भारत के स्वस्थ जीवनशैली के आदर्शों को फैलाना था। यह प्रस्ताव एक सशक्त कूटनीतिक कदम साबित हुआ, और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने वैश्विक स्तर पर अपने स्वास्थ्य और जीवनशैली के आदर्शों को प्रस्तुत किया, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि हुई (Government of India, 2015)।
2. **आयुर्वेद**: भारत ने अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों, जैसे आयुर्वेद, को वैश्विक मंच पर पेश किया। आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की, जिससे यह चिकित्सा पद्धति विश्वभर में लोकप्रिय हो गई। आयुर्वेद के लाभों को न केवल भारत में, बल्कि पश्चिमी देशों में भी स्वीकार किया गया, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिला।
3. **बॉलीवुड**: भारतीय फिल्म उद्योग, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, ने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में प्रसारित किया। बॉलीवुड फिल्मों में भारतीय संगीत, नृत्य, और परंपराओं को दर्शाया जाता है, जो दुनियाभर के दर्शकों को आकर्षित करता है। भारतीय फिल्मों ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के प्रति सकारात्मक छवि बनाई है। बॉलीवुड ने विशेष रूप से मध्य-पूर्व, एशिया, और पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति के प्रभाव को फैलाया है।

डिजिटल डिप्लोमेसी की पहलें: भारत की डिजिटल कूटनीति : डिजिटल कूटनीति या डिजिटल डिप्लोमेसी एक ऐसी कूटनीतिक प्रक्रिया है जिसमें सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके देशों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। डिजिटल कूटनीति पारंपरिक कूटनीति के मुकाबले अधिक गतिशील, त्वरित और सुलभ है। इसके माध्यम से एक राष्ट्र अपनी नीतियाँ, विचार और सांस्कृतिक धरोहर को जल्दी और प्रभावी रूप से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर सकता है (Van Ham, 2013)।

भारत ने डिजिटल कूटनीति के माध्यम से अपने वैश्विक संवाद को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का उपयोग करके न केवल अपने देशवासियों से संवाद किया, बल्कि वैश्विक समुदाय से भी संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज दुनिया भर के नेताओं और नागरिकों के साथ एक संवाद का माध्यम बना।

1. **ग्लोबल डिप्लोमेसी**: भारत ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संवाद स्थापित किया है। ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत की दृष्टि और नीतियों को प्रस्तुत किया। डिजिटल कूटनीति के इस रूप ने भारत को वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने और अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का अवसर दिया (Cohen, 2017)।
2. **G20 अध्यक्षता**: भारत ने 2023 में G20 अध्यक्षता संभाली और इस दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय समावेशन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। डिजिटल कूटनीति के माध्यम से भारत ने डिजिटल भुगतान, डिजिटल बुनियादी ढांचा और वित्तीय समावेशन के मुद्दों पर वैश्विक चर्चाएँ आयोजित की। यह पहल न केवल भारत के लिए एक कूटनीतिक विजय थी, बल्कि इसे वैश्विक समुदाय के लिए भी एक अवसर बना, जिससे डिजिटल दुनिया में बेहतर समावेशन संभव हो सके (Government of India, 2023)।

3. **कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल कूटनीति**: कोविड-19 महामारी के समय भारत ने डिजिटल कूटनीति का प्रभावी उपयोग किया। भारत ने न केवल अपनी स्वास्थ्य नीतियाँ साझा कीं, बल्कि कोविड-19 वैक्सीन के वितरण के लिए अन्य देशों से संपर्क किया। ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, भारत ने वैश्विक समुदाय से सहयोग की अपील की और अपनी स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत किया (Ministry of External Affairs, 2020)।

भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। सांस्कृतिक कूटनीति ने भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में प्रस्तुत किया है, जबकि डिजिटल डिप्लोमेसी ने भारत को वैश्विक कूटनीतिक मंच पर एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया है। जोसेफ नाय और अन्य विचारकों के सिद्धांतों के अनुसार, जब कोई राष्ट्र अपनी संस्कृति, राजनीतिक आदर्शों और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करता है, तो वह वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूती प्रदान करता है।

5.चुनौतियाँ और आलोचनाएँ : डिजिटल डिप्लोमेसी ने वैश्विक कूटनीति के दृष्टिकोण को बदल दिया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ प्रमुख चुनौतियाँ और आलोचनाएँ भी उत्पन्न हुई हैं। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना डिजिटल कूटनीति का पूर्ण और प्रभावी उपयोग करना मुश्किल हो सकता है। इस खंड में हम डिजिटल डिप्लोमेसी से संबंधित चुनौतियों जैसे डिजिटल डिवाइड, सूचना युद्ध, और राजनीतिक प्रभाव को विस्तार से समझेंगे।

डिजिटल डिवाइड: विभिन्न देशों और समुदायों के बीच डिजिटल संसाधनों की असमानता

डिजिटल डिवाइड वह स्थिति है जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों, विशेष रूप से विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल संसाधनों और इंटरनेट की पहुँच में बड़ा अंतर है। यह अंतर न केवल डिजिटल अवसंरचना (इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर) के संदर्भ में, बल्कि डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट उपयोग के संदर्भ में भी दिखाई देता है। यह असमानता वैश्विक संवाद और डिजिटल कूटनीति की प्रभावशीलता को बाधित करती है, क्योंकि केवल कुछ ही देश पूरी तरह से डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं, जबकि अन्य देश इससे वंचित रह जाते हैं (Van Ham, 2013)।

जोसेफ नाय (Nye, 2004) के अनुसार, सॉफ्ट पावर के सिद्धांत में यदि एक राष्ट्र की कूटनीति का आधार केवल डिजिटल कूटनीति है, तो यह समस्या और बढ़ सकती है। विकासशील देशों जैसे भारत, अफ्रीका, और लैटिन अमेरिकी देशों में डिजिटल अवसंरचना की कमी है, जो उन्हें डिजिटल डिप्लोमेसी के माध्यम से अपनी कूटनीतिक छवि को सुदृढ़ करने में मुश्किलें पैदा करती है। डिजिटल डिवाइड से जुड़े आंकड़े यह बताते हैं कि इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की पहुँच में अंतर केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक कूटनीतिक असमानता को भी दर्शाता है (SAIS Review, 2020)।

भारत जैसे देशों में, जहाँ डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल व्यापक रूप से बढ़ रहा है, वहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की पहुंच सीमित है, जिससे देश की डिजिटल डिप्लोमेसी की शक्ति प्रभावित होती है। इसके समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साझेदारी की आवश्यकता है, ताकि हर देश को समान डिजिटल अवसर मिल सकें (Government of India, 2020)।

सूचना युद्ध: डिजिटल प्लेटफार्म्स पर गलत सूचना और प्रोपेगेंडा का प्रसार : सूचना युद्ध वह प्रक्रिया है जिसमें सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल गलत जानकारी, अफवाहों और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जाता है। डिजिटल डिप्लोमेसी के दायरे में यह एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी और भ्रामक जानकारी बेहद तेजी से फैलती है, जो एक राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय छवि को धूमिल कर सकती है। रूस और अमेरिका के

उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने चुनावों को प्रभावित किया। रूस ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर विभिन्न प्रोपेगेंडा फैलाए, जिससे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया (Tufekci, 2017)।

भारत में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना का प्रसार एक बड़ी चुनौती बन चुका है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और प्रोपेगेंडा फैला, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता था। यही नहीं, सरकार और राजनीतिक दल भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नीतियों को प्रस्तुत करते हुए अक्सर गलत सूचना के प्रसार को बढ़ावा देते हैं (Tufekci, 2017)।

इस प्रकार, डिजिटल डिप्लोमेसी के तहत झूठी सूचना का प्रसार न केवल घरेलू राजनीति में बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी गहरी चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकारों को एक मजबूत और पारदर्शी नीति की आवश्यकता है, जिससे कि गलत सूचना का प्रसार रोका जा सके और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अधिक जिम्मेदार बनाया जा सके (Tufekci, 2017)।

राजनीतिक प्रभाव: डिजिटल डिप्लोमेसी के माध्यम से घरेलू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय छवि पर प्रभाव :

डिजिटल डिप्लोमेसी का एक और पहलू यह है कि यह घरेलू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय छवि दोनों पर प्रभाव डाल सकती है। जब कोई देश अपने घरेलू मुद्दों को सार्वजनिक करता है, तो इसका असर उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश अपनी आंतरिक राजनीति में संघर्ष या विवाद का सामना कर रहा है, तो इसका प्रभाव उसकी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और संबंधों पर भी दिखाई दे सकता है। डिजिटल प्लेटफार्म्स पर यह प्रक्रिया और भी तीव्र हो जाती है, क्योंकि देश की नीतियों, विवादों और विवादास्पद मामलों की जानकारी तुरंत पूरी दुनिया तक पहुँच जाती है।

चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को दबाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इसके माध्यम से, उसने अपने घरेलू विवादों को दुनिया से छिपाने का प्रयास किया, जबकि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी छवि को नियंत्रण में रखा। इसी प्रकार, चीन ने डिजिटल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर एक नियंत्रित और सकारात्मक छवि पेश करने का प्रयास किया, जिससे उसकी कूटनीति की दिशा और अधिक सशक्त हुई (Zeng, 2020)।

भारत भी एक उभरता हुआ देश है, जहां सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल के माध्यम से न केवल भारत की नीतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, बल्कि समय-समय पर घरेलू राजनीति की दिशा भी सामने आती है। डिजिटल डिप्लोमेसी के माध्यम से यदि किसी देश के घरेलू विवाद और मुद्दे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रकट होते हैं, तो इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे उसकी वैश्विक छवि को नुकसान हो सकता है (Van Ham, 2013)।

डिजिटल डिप्लोमेसी में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड, सूचना युद्ध, और राजनीतिक प्रभाव। इन चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए देशों को वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। डिजिटल डिवाइड की समस्या को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि सभी देशों को समान अवसर मिले। सूचना युद्ध को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। राजनीतिक प्रभाव से बचने के लिए, देशों को अपने घरेलू मुद्दों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

डिजिटल डिप्लोमेसी ने वैश्विक कूटनीति को नया आयाम दिया है, लेकिन इसके प्रभावी उपयोग के लिए इन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना अनिवार्य है। यदि इन मुद्दों पर सही तरीके से ध्यान दिया जाए, तो डिजिटल डिप्लोमेसी भविष्य में वैश्विक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती

है।

6.निष्कर्ष : डिजिटल डिप्लोमेसी ने कूटनीति के पारंपरिक रूपों में एक नया आयाम जोड़ा है और वैश्विक संवाद को तेज, प्रभावी और पारदर्शी बनाया है। इसके माध्यम से देशों के लिए अपनी नीतियों और विचारों को तत्काल और व्यापक रूप से साझा करने का अवसर उत्पन्न हुआ है। हालांकि, यह एक शक्तिशाली कूटनीतिक उपकरण साबित हुआ है, इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। डिजिटल डिवाइड, सूचना युद्ध और राजनीतिक प्रभाव जैसी समस्याएँ डिजिटल डिप्लोमेसी की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं और वैश्विक कूटनीतिक संबंधों में असमानता और अस्थिरता उत्पन्न कर सकती हैं।

डिजिटल डिवाइड का मुद्दा खासकर विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनकी डिजिटल संसाधनों और इंटरनेट की पहुँच में असमानता उनके कूटनीतिक प्रभाव को सीमित करती है। इसके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है, ताकि सभी देशों को समान अवसर मिल सके। सूचना युद्ध के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को सख्त नीतियाँ और प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करना होगा। राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में, डिजिटल डिप्लोमेसी का उपयोग देशों की घरेलू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय छवि पर गहरे प्रभाव डाल सकता है, जिससे इनका संवेदनशीलता से प्रबंधन आवश्यक हो जाता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, डिजिटल डिप्लोमेसी ने वैश्विक कूटनीति के परिप्रेक्ष्य को समृद्ध किया है और भविष्य में यह कूटनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी हिस्सा बन सकता है। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए और डिजिटल संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो डिजिटल डिप्लोमेसी न केवल देशों के बीच संवाद को बेहतर बनाएगी, बल्कि वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में एक नई क्रांति का कारण बनेगी।

संदर्भ :

1. कोहेन, आर. (2017). डिजिटल डिप्लोमेसी: सिद्धांत, रणनीतियाँ और दृष्टिकोण. रूटलेज।
2. भारत सरकार. (2015). International Day of Yoga: Celebrating Yoga for Global Harmony. विदेश मंत्रालय।
3. भारत सरकार. (2023). India's G20 Presidency: Digital Diplomacy and Financial Inclusion. विदेश मंत्रालय।
4. नाय, जे. एस. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. Public Affairs.
5. वैन हैम, पी. (2013). "Digital Diplomacy: The New Frontier in Foreign Policy". Journal of Public Diplomacy, 8(1), 1-11।
6. लैसवेल, एच. डी. (1950). The Structure and Function of Communication in Society. The Communication of Ideas.
7. लेवी-स्त्रॉस, सी. (1955). Structural Anthropology. Basic Books.
8. जोन्स, एस. (2021). "Digital Divide and the Role of Digital Diplomacy in Global Politics". SAIS Review of International Affairs, 40(1), 89-104.
9. तुफेक्सी, ज़. (2017). Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. Yale University Press.
10. SAIS Review. (2020). "The Impact of Digital Divide on Diplomacy". SAIS Review of International Affairs, 39(2), 145-156.
11. ज़ेंग, जे. (2020). "Digital Diplomacy and State Power: The Case of China". Journal of Asian Politics, 15(3), 210-224।
12. हेननेसी, पी., और ब्राउन, सी. (2018). Digital Diplomacy: The Impact of Social Media on Global Politics. Digital Diplomacy Journal.
13. भारत सरकार. (2020). Digital Diplomacy: India's Approach during COVID-19. Ministry of External Affairs.

•